• पहल...

एचआरटीसी ने शुरू की इनामी योजना

शिमला : हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से बसों में कैशलैस सुविधा को बढ़ावा देने वाले परिचालकों के लिए इनामी योजना शुरू की है। कैशलैस सुविधा को बढ़ावा देने वाले परिचालकों को हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन इनाम देकर सम्मानित करेगा। कैशलैस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए निगम ने परिचालकों के लिए इनामी योजना शुरू की है। निगम प्रबंधन की यह इनामी योजना पहली अपैल लागू मानी जाएगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। इस बीच निगम डिवीजन स्तर पर जो परिचालक कैशलैस सुविधा को लेकर बेहतर कार्य करेंगे, उन परिचालकों को इनाम देकर निगम प्रबंधन सम्मानित करेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदेश भर में 12 डिपुओं में नई ई-टिकटिंग मशीनों में कैशलैस सुविधा दी जा रही है, जिसमें परिचालक बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। वर्तमान समय में प्रदेश के 12 डिपुओं में नई ई मशीनों से कैशलैस सुविधा दी जा रही है, जिसमें शिमला में 131 मशीनों का प्रयोग हो रहा है।

इसी तरह बिलासपुर में 100, धर्मशाला में 55, तारादेवी डिपो में 64, हमीरपुर में 120, मंडी में 80, नगरोटा बगवां में 25, पालमपुर में 80, सुंदरनगर में 80, नाहन में 40, धर्मपुर में 40 और सरकाघाट में 40 मशीनें काम कर रही हैं। वहीं अन्य डिपुओं में भी जल्द नई ई-मशीनें दी जाएंगी।

उधर, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि एचआरटीसी की बसों में कैशलैस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बस परिचालकों के लिए इनामी योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक बसों में बेहतरीन सेवाएं देने वाले बस परिचालकों को इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा।

एचआरटीसी प्रबंधन ने बस परिचालकों के लिए पहला इनाम पांच हजार रुपए की कीमत का जूसर मिक्सर एंड ग्राइंडर और कूलर रखा है। इसके अलावा दूसरा इनाम तीन हजार रुपए का इंडक्शन कुकर और पांच लीटर तक प्रैशर कुकर होगा। वहीं तीसरे इनाम के रूप में दो हजार रुपए का ट्रॉली बैग या सिलिंग फैन रखा है।

• परेशानी...

शिमला में गहरा सकता है जल संकट

शिमला : पहाड़ों की रानी शिमला में आने वाले दिनों में पानी का संकट गहरा सकता है। शिमला शहर को पानी देने वाली गिरी-गुम्मा खड्ड में जलस्तर कम हो गया है। शिमला शहर में सबसे ज्यादा पानी इन दोनों परियोजनाओं से आ रहा है, लेकिन बारिश न होने और गर्मी ज्यादा पड़ने से परियोजनाएं सूखना शुरू हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में काफी कम पानी रह गया है।

जल प्रबंधन निगम हर रोज गुम्मा परियोजना से 22 एमएलडी तक पानी की सप्लाई करता था, लेकिन अब 19 एमएलडी पानी ही शिमला पहुच रहा है। इसके अलावा गिरी परियोजना से जहां पहले 17 एमएलडी पानी मिलता था वहीं, अब 11 एमएलडी पानी वीरवार को शिमला पहुंचा है. शिमला शहर में हर रोज 45 एमएलडी तक पानी की जरूरत रहती है। वीरवार को शिमला में सभी परियोजनाओं से केवल 33 एमएलडी पानी ही मिल पाया है, जिससे कई क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है, जिन क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है वहां पानी के टैंकर्स से जल प्रबंधन निगम सप्लाई कर रहा है। शिमला के कुछ क्षेत्र पानी की किल्लत झेल रहे हैं।

जल प्रबधन के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट साहिल शर्मा ने कहा कि इस बार सर्दियों में बर्फबारी काफी कम हुई है ओर गर्मियों में भी बारिश नहीं हो रही है, जिससे पेयजल परियोजनाओं में पानी का स्तर कम हो रहा है। बावजूद इसके जल प्रबंधन निगम दिन-रात काम कर रहा है और शिमला शहर में लोगों को पानी देने का हर संभव प्रयास कर रहा है. 2018 में जिस तरह से पार्टी का संकट आया था उस समय भी पानी के स्रोतों में पानी की कमी हो गई थी, लेकिन इस बार उससे ज्यादा पानी कम हो गया है। बावजूद इसके शहर में पानी लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसी भी तरह की पैनिक जैसी स्थिति नहीं है।

कम्युनिकेशन एक्सपर्ट साहिल शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात रहते हैं तो जल प्रबंधन निगम एक दिन छोड़कर लोगों को पानी दे सकता है। जिन क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है वहां पर पानी के टैंकर्स के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है. अभी शिमला में पेयजल संकट के हालात नहीं है. दो दिन तक पानी ना आने पर 24X7 काम करने वाले कंट्रोल रूम में 14420 हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकता है। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि पानी को बर्बाद ना करें और जरूर के हिसाब से ही इसका प्रयोग करें।

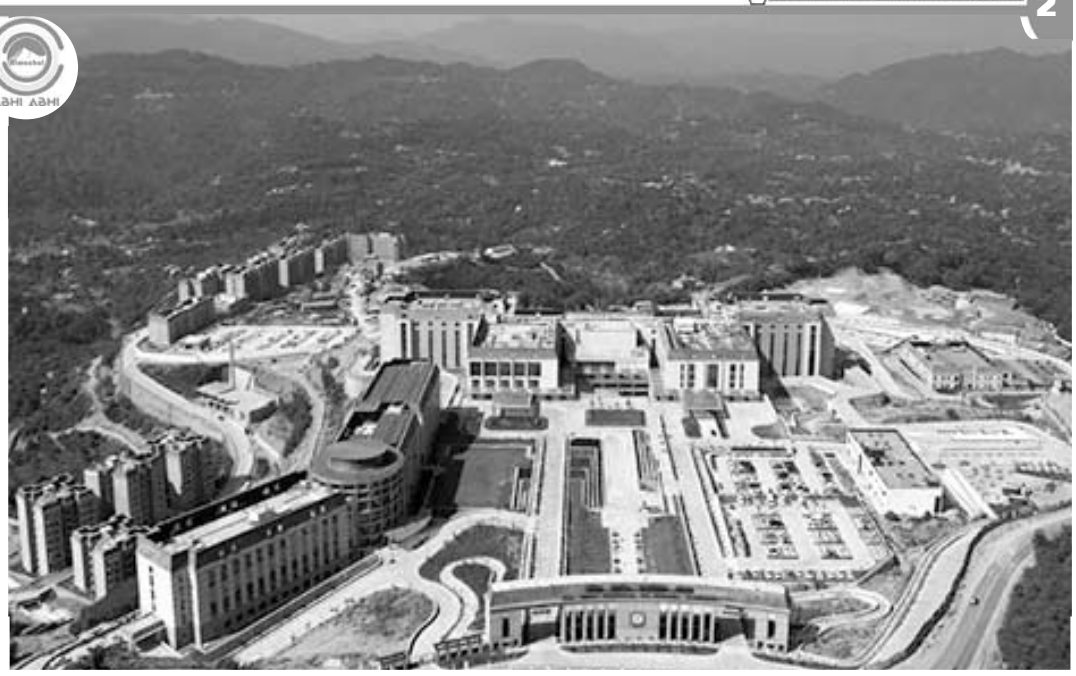

बिलासपुर एम्स में मिलेंगी ये सुविधाएं

इस एम्स में अभी कई नए विभाग यहां पर खुलना और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होना बाकी है। साथ ही मशीनरी आदि भी स्थापित होगी। इसके बाद लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अन्य राज्यों में जाने से छुटकारा मिलेगा।

एम्स दिल्ली जैसी सुविधाएं यहां मिलने के बाद प्रदेश के लोगों को नजदीक ही इलाज होगा और अन्य राज्यों में न जाने से धन की बचत भी होगी...

● सुभाष/बिलासपुर

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बड़ी उपलब्धि है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के एक छोर में बने इस संस्थान से हिमाचल ही नहीं पड़ोसी राज्य पंजाब के लोगों को भी लाभ मिलेगा। वर्तमान में यहां कई सेवाएं शुरू हुई हैं जबकि केंद्र सरकार की सहायता से यहां पर चिकित्सा सुविधाओं में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

प्रदेश में पहली बार किसी बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम समय में पूरा किया गया है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और साल 2022 में इसका उद्घाटन किया था।

इस एम्स में अभी कई नए विभाग यहां पर खुलना और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होना बाकी है। साथ ही मशीनरी आदि भी स्थापित होगी। इसके बाद लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अन्य राज्यों में जाने से छुटकारा मिलेगा।

एम्स दिल्ली जैसी सुविधाएं यहां मिलने के बाद प्रदेश के लोगों को नजदीक ही इलाज होगा और अन्य राज्यों में न जाने से धन की बचत भी होगी।

बिलासपुर में एम्स खुलने से पड़ोसी राज्यों के लोग भी यहां आसानी से पहुंचकर इलाज करवा सकेंगे। एम्स बिलासपुर में जल्द ही पल्मनेरी मेडिसिन समेत चार विभागों में शीघ्र ओपीडी सुविधा शुरू होगी।

एम्स प्रबंधन ने चारों विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भरने की तैयारी कर ली है। एम्स प्रबंधन पल्मनेरी मेडिसिन, पीएमआर, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलाजी व सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलाजी ओपीडी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन विभागों के शुरू होने से लोगों को आइजीएमसी शिमला व पीजीआइ चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा।

247 एकड़ (99.96 हेक्टेयर) भूमि में फैले एम्स बिलासपुर में वर्तमान में 21 विभाग काम कर रहे हैं। इस साल संस्थान में कैथ लैब स्थापित की गई है जिससे हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी व स्टंट डालने जैसी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

हृदय रोग से पीड़ित मरीजों में पेसमेकर लगाने व बच्चों के हृदय में छेद को डिवाइस से बंद करने सहित कई गंभीर बीमारियों का इलाज यहां हो रहा है। यहां पर अभी 597 बिस्तर की सुविधा है।

एम्स बिलासपुर में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, बाल रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, चर्म रोग, ईएनटी, नेत्र रोग, एंडोक्रिनोलाजी, मनोरोग, हृदय चिकित्सा, मेडिकल आन्कोलाजी, दंत रोग, रेडिएशन आन्कोलाजी, सर्जरी आन्कोलाजी, प्लास्टिक सर्जरी, नियोनेटोलाजी, क्लीनिकल इम्यूनोलाजी, स्मेटोलाजी (गठिया) पीएसी, नेफ्रोलाजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूरोलाजी, मनोरोग, सीटीवीएस सर्जरी आन्कोलाजी, न्यूरो सर्जरी, इंटरवेंशनल रेडियोलाजी, यूरोलाजी, एनसीडी (डायबिटिक क्लीनिक) जैसे विभागों में ओपीडी की सुविधा मिल रही है।

तीसरी बार कर्ज लेगी सरकार, 1200 करोड़ के लिए किया आवेदन

शिमला : देश में अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद राज्य सरकार प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान करने के लिए 1200 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। इस तरह नए वित्त वर्ष में सरकार तीसरी बार कर्ज ले रही है। इससे पहले सरकार ने गत अप्रैल माह में 1000 करोड़ रुपए और इसी माह 700 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। अब सरकार 2 अलग-अलग मदों में कर्ज लेने के लिए आवेदन कर रही है, जिसमें 700 करोड़ रुपए 2 वर्ष और 500 करोड़ रुपए 10 वर्ष की अवधि के लिए लिए जा रहे हैं। इसके अनुसार सरकार को 700 करोड़ रुपए 5 जून, 2036 और 500 करोड़ रुपए 5 जून, 2034 को ब्याज सहित लौटाने होंगे। वर्तमान सरकार को दिसम्बर, 2024 तक 6200 करोड़ रुपए कर्ज लेने की अनुमति मिली है। इसमें से अब 5 जून तक राज्य सरकार 2900 करोड़ रुपए कर्ज ले लेगी। यानी अब दिसम्बर माह तक 3300 करोड़ रुपए तक कर्ज लिया जा सकेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने बीते वित्तीय वित्त वर्ष में करीब 8372 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। अब सरकार की तरफ से 1200 करोड़ रुपए कर्ज लेने के बाद प्रदेश सरकार पर करीब 84200 करोड़ रुपए कर्ज हो जाएगा।

• हाईकोर्ट...

नियमित करने के आदेश

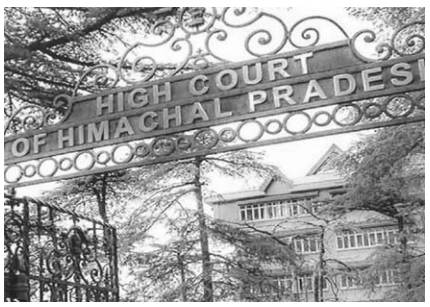

शिमला। हाई कोर्ट ने 8 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने पर नियमितिकरण करने की मांग से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए कहा कि सरकार अपनी उच्च स्थिति का लाभ उठाते हुए कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकती। नगर निगम शिमला के दो सेनेटरी इंस्पेक्टरों को 8 वर्ष का अनुबंध काल पूरा करने पर उन्हें नियमित करने के आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि निस्संदेह, नगर निगम शिमला राज्य की एक शाखा होने के नाते सामाजिक विवेक वाला एक आदर्श नियोक्ता है। सामाजिक विवेक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। इसलिए सरकार को आवश्यक रूप से ऐसे साधनों और तरीकों को अपनाकर अपने कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए उच्च ईमानदारी और स्पष्टवादिता के साथ ऐसे सामाजिक विवेक के साथ आचरण करना चाहिए, जो उचित हों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार हों।

• भरमौर में जला मकान...

भरमौर : भरमौर उपमंडल की ग्राम पंचायत पूलन में एक मकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आरंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। फिलहाल जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल सकेगा। स्थानी पंचायत के स्वयंसेवी अंग्रेज कपूर ने बताया कि पूलन गांव के जैसी पुत्र दर्जी के मकान में आग लग गई। इससे भीतर चल रही उन पिंजाई मशीन, छोटी आरा मशीन और आटा चक्की तथा रखा सारा समान जल गया।